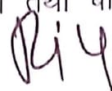


पुनश्च कोई भी विक्रय पत्र जो 100/- रुपये से अधिक की सम्पत्ति का हो उसका रजिस्टर्ड होना कानूनन जरूरी है। अतः यह तनकी भी विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
6. आया विवादित आराजीयात सहखातेदारी की है तथा बगैर बंटवारा व अलग खातेदारी की घोषणा चाहे बगैर दावा जिन धाराओं में पेश किया है, वह चलने योग्य नहीं है, इसलिए दावा खारिज होने योग्य है ? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी के अनुसार विवादित आराजीयात का वादी सेपरेट खातेदार दर्ज है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हिस्सा दर्ज नहीं है अतः यह तनकी भी विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

7. अनुतोष:- उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी विवादित भूमि का सेपरेट खातेदार है जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा गैर कानूनी है, अतः वादी धारा 183 व 188 आरटी0एक्ट के तहत प्रतिवादीगण को विवादित भूमि से वेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। अतः दावा वादी के पक्ष में डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी की भूमि ग्राम बाढ भूदर के खसरा नं0 3/1, 29/1, 110 से वेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 11 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की उक्त खातेदारी की भूमि में फसल काश्त करने में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना तो स्वयं करे ना ही किसी दीगर से करावे। इसी अनुसार पर्या डिक्री जारी हो। आदेश आज दिनांक 25.04.2018 को सारे इजलारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(राजपाल यादव आरपीएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

धारा 188 आर०टी०एक्ट के तहत चलने योग्य नहीं है। गांव बाढ़ भूदर से उसका हर किस्म का सम्बन्ध खत्म हो जाने के कारण हम प्रतिवादीगण केशूलाल, कमल, महेश, मदन से लिए कर्ज को ना दे पाने पर उक्त विवादित जमीनों का बेचान हमारे नाम करने का मुआहिदा लिखि 100/- के स्टॉम्प पर दिनांक 23.10.2010 को किया। धारा 183 आर०टी०एक्ट के तहत भी दावे में कोई ना तो तथ्य लिखा है ना ही सही हालात लिखे हैं। विवादित आराजीयात सहखातेदारी की भूमि है, सहखातेदारान को दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए दावा वादी खारिज होने योग्य है।

वाद तथ्य, जवाबदावा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर सात तनकीयात कायम की गई। वकील वादी ने साक्ष्य में वादी कांडू पीडब्ल्यू-1 का शपथ पत्र पेश किया जिससे जिरह रिकार्ड की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वकील वादी ने नकल जमाबंदी ग्राम बाढ़ भूदर सम्बत् 2068-71, प्रथम सूचना रिपोर्ट की नकल, अपराध विवरण फॉर्म की नकल, नकल नवशा मोका, बयान गवाहान की प्रमाणित प्रति, अन्तिम रिपोर्ट फॉर्म पेश किये हैं। प्रतिवादीगण ने कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में 100/- स्टॉम्प पर लिखी तहरीर की फोटो प्रति एवं लीगल नोटिस की फोटोप्रति पेश की है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा, जवाबदावा, उपलब्ध दस्तावेजों व बहस के अनुरार तनकीवाईज विवेचन निम्न प्रकार है:-

1. आया मौजा बाढ़ भूदर तहसील सपोटरा में स्थित आराजीयात खसरा नं० 3/1 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं० 29/1 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं० 110 रकबा 15 बिस्वा वादी की खातेदारी है ? इस तनकी को सावित करने का भार वादी पर है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सं० 2068-71 व 2072-75 के अनुसार ग्राम बाढ़ भूदर की विवादित आराजीयात वादी की रिकार्डेड खातेदारी में दर्ज है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
2. आया वादी अपनी खातेदारी की आराजीयात से प्रतिवादी सं० 1 ता 11 को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है ? इस तनकी को भी सावित करने का भार वादी पर है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्बत् 2068-71 व 2072-75 के अनुसार वादी विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार हैं। उक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा दर्ज नहीं है। वादी की सेपरेट खातेदारी की भूमि पर प्रतिवादीगण को कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दान/वसीयत/हक त्याग/बेचान/डिक्री आदि कानूनन मान्य दस्तावेजों के आधार पर ही किसी व्यक्ति का किसी भूमि पर कब्जा लेने का अधिकारी होता है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह सावित हो सके कि उनका विवादित भूमि पर कब्जा कानूनन सही है। वादी द्वारा कानूनन वंटवारे की डिक्री कराकर खाता पृथक कराया है तथा इसी आधार पर विवादित आराजीयात का वादी एक मात्र रिकार्डेड खातेदार दर्ज हुआ है। सेपरेट खातेदार की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना किसी वैध कारण के कब्जा करना कानूनन गलत है। अतः उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात पर कब्जा गैर कानूनी है, जिनको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने का वादी अधिकारी है। इसलिए यह तनकी वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
3. आया वादी प्रतिवादी सं० 1 ता 11 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है ? इस तनकी को सावित करने का भार भी वादी पर है। तनकी सं० 2 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात वादी की सेपरेट खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा गैर कानूनी है। अतः वादी प्रतिवादी सं० 1 ता 11 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
4. आया विवादित आराजीयात पर वादी का कब्जा काश्त नहीं होने के कारण दावा अन्तर्गत धारा 188 आर०टी०एक्ट चलने योग्य नहीं है, इसलिए दावा वादी खारिज होने योग्य है ? इस तनकी को सावित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादी ने स्वयं अपने वाद तथ्यों में यह अंकित किया है कि मेरी खातेदारी की भूमि पर प्रतिवादीगण ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, इसी कारण वादी ने वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183, 188 के अन्तर्गत पेश किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
5. आया विवादित भूमियां प्रतिवादीगण केशूलाल, कमल, महेश, मदन ने जरिये तहरीर स्टॉम्प रुपये 100/- पर कय की है ? इस तनकी को सावित करने का भार प्रतिवादीगण को है। पत्रावली में संलग्न स्टॉम्प तहरीर में पैसे उधार लेने का उल्लेख है, भूमि बेचान करने का कोई विवरण अंकित नहीं है, पैसे का उधार लेने देन सिविल प्रकरण है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठारीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किरम	ता0दायरा	ताशीख निर्णय
18/15	दावा	17.06.2013	25.04.2018

काडू पुत्र कज्जू आयु 62 साल जात वैरवा निवासी बाढ भूदर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

वनाम

-वादीगण

1. केशूलाल ।
2. कमल ।
3. महेश । पि0 रामहेत
4. मदन ।
5. बादामी पत्नि केशूलाल
6. गंगासहाय पुत्र केशूलाल
7. गुड्डू पुत्र केशूलाल
8. पीतम पुत्र केशूलाल
9. लच्छो पत्नि मदन
10. गुड्डी पत्नि महेश
11. गीता पत्नि कमल
12. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा।

राभी जातिगण वैरवा निवासी बाढ भूदर तह0 सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित:- श्री राजाराम मीना एड0 वकील वादी।

श्री नदीम खॉन एड0 वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि वादी ने एक वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खरारा नं0 3/1 रकबा 14 बिसवा, ख0नं0 29/1 रकबा 12 बिसवा, ख0नं0 110 रकबा 15 बिसवा कुल कित्ता 3 कुल रकबा 02 बीघा 01 बिसवा वाके ग्राम बाढ भूदर तहसील सपोटरा वादी की खातेदारी की आराजीयात है, जिससे प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है। वादी गरीब व बुजुर्ग व्यक्ति है जबकि प्रतिवादीगण चतुर व चालाक किरम के व्यक्ति है। दिनांक 11.06.2015 को प्रतिवादीगण ने लट्ट के बल से मुझ वादी की आराजीयात को जोत डाला है, वादी ने मौके पर पहुँच कर प्रतिवादीगण से हाथ जोड़कर मना किया तो प्रतिवादी सं0 1 ता 11 हाथों मे लाटी गडारी लेकर मारने पीटने पर उतारु हो गये और एलानिया कहने लगे कि यह जमीन को तुझे कभी भी नही जोतने देंगे, इस जमीन को हमे देदे नही तो हम लट्ट के बल से लेकर रहेगें। प्रतिवादीगण राज कानून से निडर व्यक्ति है। वादी का कमाई का एकमात्र जरिया कृषि है, कृषि के अलावा अन्य कोई चारा नही है। इसलिए वादी ने अपनी खातेदारी की भूमि से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाकर वादी को कब्जा दिलाये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निपेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज कर तलवी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण ने जरिये वकील अपना जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वादी ने दावा हाजा कतई गलत हालात बनाकर हम प्रतिवादीगण को तंग परेशान करने की वदनियति से पेश किया है। दो लाख पांच हजार की लम्बी रकम ऐठने के लिए यह दावा गलत पेश किया है। वादी हम केशूला, कमल, महेश, मदन का खास काका है इस तथ्य को दावा मे छुपाया गया है तथा यह भी छुपाया गया है कि वादी 40 साल से मय गृहस्थी गढी समेल तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर मे रहता है एवं वही पर इसके व इसके लड़के के घर बने हुए है, काश्त जमीने है, राशन कार्ड बना हुआ है, वोटर लिस्ट मे नाम लिखा हुआ है। वादी को अपनी घरु आवश्यकता के लिए रुपयों की आवश्यकता थी इसलिए उसके गढी समेल के पते पर भेजा जा चुका है। पैसा नही चुका पाने की सूरत मे वादी स्वयं ने हमे कब्जा दिया है। अब यह दावा गलत तथ्यों पर सच्चाई को छुपाते हुए वदनियति से पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। विवादित आराजीयात पर वादी का कब्जा काश्त नही होने के कारण दावा